



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217]  
No. 217]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 1983/पौष 9, 1905  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 1983/PAUSA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

**श्रम और पुनर्वास मंत्रालय**

(श्रम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर 1983

**प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता संबंधी योजना**

संख्या : एल-56011/1/83-डैस्क I(बी) :—भारत सरकार के संकल्प संख्या एस-61011/4/75-डैस्क I (बी), तारीख 30 अक्टूबर, 1975 द्वारा उद्योग में शाप-फ्लोर और प्लांट स्तरों पर श्रमिकों की सहभागिता संबंधी योजना सरकार ने 30 अक्टूबर, 1975 को शुरू की थी और इसे केवल सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रों के विनिर्माण और खनन एककों तथा विभागीय रूप से चलाई जा रही ऐसी यूनिटों पर लागू किया गया था जिनमें 500 या उससे अधिक श्रमिक नियोजित हों। भारत सरकार के संकल्प संख्या एल-56025/4/75-डैस्क 1 (बी), तारीख 4 जनवरी, 1977 द्वारा सरकार ने श्रमिक सहभागिता सम्बन्धी अन्य योजना सरकारी क्षेत्र में उन वाणिज्यिक और सेवा संगठनों में शुरू की, जो बड़े पैमाने पर लोक कार्य करते हों ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। सरकार ने उपर्युक्त योजनाओं

की कार्य-प्रणाली का पुनरीक्षण किया है। इस पुनरीक्षण और अब तक प्राप्त किए गए अनुभव को दृष्टि में रखते हुए, सरकार ने निर्णय किया है कि इस योजना के स्थान पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों में सहभागिता की नई व्यापक योजना शुरू की जाए। इस उद्देश्य हेतु, निम्न-लिखित योजना तैयार की गई है :—

**प्रस्तावना**

1. यह योजना केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर लागू होगी लेकिन उन उपक्रमों पर लागू नहीं होगी जिन्हें श्रम विभाग के साथ परामर्श करके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा योजना के प्रचालन में छूट प्रदान की गई हो, परन्तु उपक्रम के स्वरूप, उन वस्तुओं, जिसका यह निर्माण कर रहा है, आदि का ध्यान रखा जाएगा।

तथापि, केन्द्रीय सरकार के किसी भी उपक्रम को, जो विभागीय रूप से चलाया जाता है, इस नई योजना में बाहर रखा जाएगा।

**योजना का ढाँचा**

2. इस योजना को सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में शाप-फ्लोर और प्लांट दोनों पर लागू किया जाएगा (सिविल

(सिवाय उन्हें छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से छूट प्रदान की गई है)। जहां तक बोर्ड स्तर पर सहभागिता का संबंध है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, (जो उपक्रम का इंचार्ज है) श्रम विभाग से परामर्श करके, उन उपक्रमों की सूची तैयार करेगा, जिन्हें वह बोर्ड स्तर पर भी इस योजना को शुरू करने के लिए उपयुक्त समझेगा इस सूची की समय समय पर पुनरीक्षा की जाएगी ताकि इसके कार्यक्षेत्र के अन्दर व्यापक अधिक से अधिक उपक्रमों को लाया जा सके।

### प्रतिनिधित्व

3. शाप-फ्लोर और प्लाट स्तरों पर श्रमिकों के प्रतिनिधित्व में कुशल और अकुशल, तकनीकी और गैर-तकनीकी जैसे श्रमिकों के विभिन्न वर्ग शामिल होंगे। प्रबन्धकीय कार्मिकों को इससे बाहर रखा जाएगा, लेकिन फोरमैन, चार्जमैन आदि जैसे पर्यवेक्षी वर्गों को इसमें शामिल किया जाएगा। शाप-फ्लोर और प्लाट स्तर मंचों पर श्रमिकों और प्रबन्धकों दोनों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रत्येक पक्ष के पांच से दस सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा जो श्रमिकों की संख्या के आकार पर निर्भर करेगा। सही संख्या का निर्धारण प्रबन्धतंत्र द्वारा उपक्रम में ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ परामर्श करके किया जाएगा। प्रबन्धतंत्र ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ भी परामर्श करेगा और सर्व सम्मति से उन सभी स्तरों पर श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के लिए पद्धति को प्रस्तुत करेगा जिस पर इस योजना को लागू किया जाएगा। मतौर पर पहुंचने के लिये यूनियन के नेताओं को राजी करने में प्रबन्धतंत्र यह बता सकता है कि ऐसे मतैक्य के अभाव में यह योजना लागू करने के काबिल नहीं होगी। प्रबन्धतंत्र और ट्रेड यूनियन नेता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहभागी मंचों में महिला का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जहां महिला श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों की संख्या का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है। प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रबन्धतंत्र के दबावों से महिलाओं की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी प्रकार से सताने या उत्पीड़न से श्रमिकों को संरक्षण प्रदान किया जा सके।

### कार्य

4. सहभागी व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित कार्य अन्तर्गत आएंगे :

(क) शाप स्तर : उत्पादन सुविधाएं, शाप में भंडार व्यवस्था, सामग्री में क्वालिटी, परिचालन समस्याएं, क्षति नियंत्रण, जोखिम, सुरक्षा समस्याएं स्तर में सुधार सफाई मासिक लक्ष्य और उत्पादन कार्यक्रम, लागत में कटौती सम्बन्धी कार्यक्रम, कार्य पद्धति बनाना और कार्यान्वित करना, डिजाइन, सामूहिक कार्य, कल्याण उपाय., विशेष रूप से शाप से संबंधित उपाय।

(ख) प्लाट स्तर :

परिचालन क्षेत्र :—

- (1) स्थानीय दशाओं को देखने हुए उत्पादकता योजनाएं बनाना
- (2) मासिक लक्ष्यों और कार्यक्रमों की योजना तैयार करना, इन्हें कार्यान्वित करना और पूरा करना तथा इनकी पुनरीक्षा करना।
- (3) सामग्री आपूर्ति और इसमें कमियां
- (4) भंडार और वस्तु सूची।
- (5) हाउस वीपिंग।
- (6) सामान्यतः उत्पादकता में सुधार और विशेष रूप से नाजुक क्षेत्रों में।
- (7) मुद्दाओं को प्रस्तावित देना और इन पर विचार करना।
- (8) कोटि और प्रोत्तोगिकी में सुधार।
- (9) मशीन का उपयोग, नए उत्पादों की जानकारी और विकास।
- (10) परिचालन निष्पादन आंकड़े।
- (11) वे मामले, जिनका शाप स्तर पर निपटारा नहीं हो पाया या जो एक से अधिक शाप से संबंधित हैं।
- (12) शाप स्तर निकायों के कार्यकरण की पुनरीक्षा।

### आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र

- (1) लाभ और हानि विवरण, तुलन-पत्र।
- (2) परिचालन व्ययों, वित्तीय परिणामों, बिक्री लागत की पुनरीक्षा।
- (3) वित्तीय शर्तों, श्रम और प्रबन्धकीय लागतों, बाजार दशाओं, आदि में प्लाट निष्पादन।

### वैयक्तिक मामले

- (1) अनुपस्थिति।
- (2) महिला श्रमिकों की विशेष समस्याएं।
- (3) श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आरम्भ और पर्यवेक्षण।
- (4) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रयासन।

### कल्याण क्षेत्र

- (1) परिचालन व्यौरा।
- (2) कल्याण योजनाओं, चिकित्सा सुविधाओं और परिवहन सुविधाओं का कार्यान्वयन।
- (3) सुरक्षा उपाय।

- (4) खेल कूद ।
- (5) आवास ।
- (6) टाउनशिप का प्रगामन कैंटीन, आदि ।
- (7) जुआ खेलने, शराब पीने, ऋण प्रस्तुता, आदि पर नियंत्रण ।

#### पर्यावरिक क्षेत्र

- (1) विस्तार कार्यकलाप और समुदाय विकास परियोजनाएं ।
- (2) प्रदूषण नियंत्रण ।

(ग) बोर्ड स्तर : बाड़े स्तर पर, श्रमिकों के प्रतिनिधि बोर्ड के सभी कार्यों में भाग लेंगे । बोर्ड को सौंपे गए विशेष कार्यों में एक कार्य शाप और प्लांट स्तर पर सहभागी मंचों के कार्य की पुनरीक्षा करना होगा ।

5. मंचों का कार्यकरण : शाप-फ्लोर और प्लांट स्तरों पर, सहभागी मंच मनेक्य द्वारा नियंत्रित लेने का प्रयास करेंगे, परन्तु जहां कोई पारस्परिक श्वीकार्य मनेक्य नहीं हो पाता, वहां वे मापले को अपने उच्च मंच में भेजेंगे ।

6. मंचों के कार्यों में संशोधन : श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच पारस्परिक मनेक्य द्वारा कार्यों के क्षेत्र में संशोधन किया जा सकता है ।

7. योजना की मानिटरींग : योजना की एक वर्ष के भीतर कार्यान्वित करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किया जाएगा । प्रत्येक उपक्रम में योजना के कार्यकरण की प्रगति की निमाही पुनरीक्षा की जाएगी ।

योजना के कार्यान्वित करने का मानिटरींग करने और समय-समय पर इसके कार्यकरण की भी पुनरीक्षा करने तथा उपपारी उपपारों का सुझाव देने के उद्देश्य से, श्रम विभाग में एक त्रिपक्षीय तंत्र स्थापित किया जाएगा ।

8. सामान्य : योजना को कानूनी समर्थन देने के लिए तत्काल कोई कानून नहीं बनाया जाएगा । तथापि ऐसी कार्यावाही पर योजना के कार्यकरण में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो जाने के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे यह योजना अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमां में प्रारम्भ करें । निजी क्षेत्र के उपक्रमां को भी यह योजना कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि योजना के कार्यकरण में अनुभव प्राप्त करने के बाद यथामय कानून बनाया जाए । अतः यह निजी क्षेत्र के भी हित में है कि इसे लाभकारी समझें और इस दिशा में शीघ्र स्वयं पहल करें ।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र (असाधारण) में सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए ।

बी०जी० देशमुख, सचिव

#### MINISTRY OF LAOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

#### RESOLUTION

New Delhi, the 30th December, 1983

#### SCHEME FOR EMPLOYEES' PARTICIPATION IN MANAGEMENT

No. L. 56011/1/83-Desk I(B).—The Scheme for Workers' Participation in Industry at shop floor and plant levels was introduced by Government on the 30th October, 1975 vide Government of India's Resolution No. S. 61011(4)/75-Desk I(B) dated the 30th October, 1975 and was made applicable only to manufacturing and mining units in the public, private and cooperative sectors, as well as those run departmentally, employing 500 or more workers. Another Scheme on Workers' Participation was introduced by the Government vide Government of India's Resolution No. L-56025/4/75-Desk I(B) dated the 4th January, 1977 in commercial and service organisations in the public sector, which have large scale public dealings, with a view to rendering better customer service. Government have taken a review of the working of the above schemes. In the light of this review and experience gained so far, Government have decided to introduce instead a new comprehensive scheme of Workers' Participation in Central Public Sector Undertakings. For this purpose the following Scheme has been drawn up :—

#### Introduction

1. The Scheme will be applicable to all Central Public Sector Undertakings except those undertakings which are given specific exemption from the operation of the Scheme by the Administrative Ministry/Department concerned in consultation with the Department of Labour, taking into account the nature of the undertaking, the products it is manufacturing etc.

Any undertaking of the Central Government which is run departmentally, however, will be excluded from this new Scheme.

#### Structure of the Scheme

2. The Scheme shall be operated both at the shop floor and plant levels in all public sector undertakings (other than those which have been specifically exempted). As regards participation at the Board level, the Administrative Ministry/Department concerned (in charge of the undertaking) will draw, in consultation with the Department of Labour, a list of undertakings which it considers would be suitable for introduction of the Scheme at the Board level also. This list will be reviewed from time to time with a view to bringing in as many undertakings as possible within its scope.

#### Representation

3. The representation of the workers at the shopfloor and plant levels would cover different categories of workers such

as skilled and unskilled, technical and non-technical. Managerial personnel would be excluded, but supervisory categories such as Foreman, Chageman etc. would be covered. Both the workers and the management will get equal representation at the shopfloor and plant level forums. Each party will have a representation of five to ten members depending on the size of the work force. The exact number would be arrived at by the management in consultation with the trade union leaders in the undertaking. The management will also consult the concerned trade union leaders and evolve through consensus the mode for representation of workers at all levels at which the Scheme would be implemented. In persuading the union leaders to reach a consensus, the management may point out that in the absence of such a consensus, the Scheme would not be capable of implementation. The management and the trade union leaders would ensure that there is adequate representation for women in the participative forums where women workers constitute 10 per cent or more of the total work force. The management would also ensure that adequate provision is made to safeguard workers' independence from management pressure so as to ensure workers' protection against any harassment or victimisation.

#### Functions

4. The participating arrangement may cover the following functions at different levels :

(a) Shop Level.—Production facilities, storage facilities in a shop, material economy, operational problems, wastage control, hazards, safety problems, quality improvement, cleanliness, monthly targets and production schedules, cost reduction programmes, formulation and implementation of work system, design group working, welfare measures related particularly to the shop.

(b) Plant Level :

##### Operational areas :—

- (i) Evolution of productivity schemes taking into account the local conditions.
- (ii) Planning, implementation, fundamental and review of monthly targets and schedules.
- (iii) Materials supply and its shortfall.
- (iv) Storage and inventories.
- (v) House-keeping.
- (vi) Improvements in productivity in general and in critical areas in particular.
- (vii) Encouragement to and consideration of suggestions.
- (viii) Quality and technological improvements.
- (ix) Machine utilisation, knowledge and development of new products.
- (x) Operational performance figures.
- (xi) Matters not resolved at the shop level or concerning more than one shop.
- (xii) Review of the working of the shop level bodies.

##### Economic and financial areas :

- (i) Profit and loss statements, balance sheets.
- (ii) Review of operating expenses, financial results, cost of sales.
- (iii) Plant performance in financial terms, labour and managerial costs, market conditions etc.

##### Personnel matter :—

- (i) Absenteeism.
- (ii) Special problem of women workers.
- (iii) Initiation and supervision of workers' training programmes.
- (iv) Administration of social security schemes.

#### Welfare areas :

- (i) Operational details.
  - (ii) Implementation of welfare schemes, medical benefits and transport facilities
  - (iii) Safety measures.
  - (iv) Sports and games.
  - (v) Housing.
  - (vi) Township administration, canteen etc.
  - (vii) Control of gambling, drinking, indebtedness etc.
- Environmental areas :
- (i) Extension activities and community development Projects.
  - (ii) Pollution control.

(c) Board Level.—At the Board level, the workers representatives will participate in all the functions of the Board. One of the special functions assigned to the Board would be reviewing the work of the shop and plant level participating forums.

5. Working of the forums.—At the shopfloor and the plant levels, the participating forums will attempt to arrive at a decision by consensus; but where no mutually acceptable consensus emerges, they will refer the matter to the next higher forum.

6. Modifications of the functions of the forums.—The scope of the functions can be modified by mutual consensus between the workers and the management.

7. Monitoring of the Scheme.—A time bound programme for implementation of the scheme within one year will be drawn up by the administrative Ministries/Departments concerned. The progress of the working of the scheme in individual undertakings will be reviewed quarterly.

In order to monitor the implementation of the scheme and also to review its working from time to time and to suggest remedial measures, a tripartite machinery will be set up in the Department of Labour.

8. General.—No legislation would be undertaken immediately to give any legislative backing to the Scheme. Such a step would, however, be considered after adequate experience has been gained in the working of the Scheme.

State Governments are requested to introduce the Scheme in their own public sector undertakings. The private sector would also be encouraged to implement the Scheme. It is the intention of the Central Government to bring legislation in due course after gaining experience in the working of the Scheme. It is, therefore, in the interest of the private sector also that they should find it advantageous to make a start of their own very early in this direction.

#### ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Cabinet Secretariat, the Prime Minister's Secretariat, all the Ministries/Departments of the Government of India, the Planning Commission, the State Governments and the Governments/Administrations of Union Territories.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary for general information.

B. G. DESHMUKH, Secy.